दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 ‖ Postal Registration No-055/Raigarh DN CG ‖ रायगढ़, मंगलवार 01 जून 2021 ‖ पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए ‖ वर्ष-03, अंक- 241

महत्वपूर्ण एवं खास

भीमा नदी में चार किशोरों की डूबने से हुई मौत

विजयपुरा (आरएनएस)। कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा से सटे लवागी में तीन किशोरियों समेत चार लोगों की भीमा नदी में डूबने से मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार लवागी में रविवार शाम भीमा नदी में तैरते समय डूबने से तीन किशोरियों समेत चार की मौत हो गई। मृतकों की पहचान आरती (13) और विट्ठल (15) दोनों सहोदर भाई-बहन और समीक्षा (14) और अर्पिता (13) दोनों सहोदर बहनें के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि आरती के शव को नदी से बाहर निकाल लिया गया और शेष अन्य शवों की तलाश जारी है। महाराष्ट्र में मंदरूप पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच कर शुरु कर दी है।

प्रदेशों और केंद्रीय संस्थानों को एम्फोटेरिसिन-बी की अतिरिक्त 30100 शीशियां आवंटित की गयीं- डी वी सदानंद गौड़ा

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डी वी सदानंद गौड़ा ने घोषणा की कि सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय संस्थानों को आज एम्फोटेरिसिन-बी की अतिरिक्त 30100 शीशियां आवंटित की गयी हैं।

एनटीपीसी ऊंचाहार ने रायबरेली जिला प्रशासन को ऑक्सीजन प्लांट सौंपा

नई दिल्ली (आरएनएस)। विद्युत मंत्रालय की महारत्न कंपनी एनटीपीसी ने कोविड के खिलाफ लड़ाई में मदद का सिलसिला जारी रखते हुए ऊंचाहार में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की है। प्लांट को रायबरेली जिला प्रशासन को सौंपा गया। एनटीपीसी द्वारा आवश्यक उपकरण और संसाधन लागू करने वाली संस्था को प्लांट के सुचारु संचालन के लिए उपलब्ध कराए गए थे। इस ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना के साथ ही तत्काल प्रभाव से जरूरतमंद लोगों को नियमित रूप से ऑक्सीजन सुविधा प्राप्त होगी। इससे पहले एनटीपीसी द्वारा ऊंचाहार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 10 ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई की गई थी। संकट की इस स्थिति में एनटीपीसी ऊंचाहार का यह कदम आशा की किरण के रूप में उभरा है ताकि ग्रामीण जनता भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधा हासिल कर सके।

12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर सुनवाई स्थगित, केंद्र ने मांगा दो दिन का समय

नई दिल्ली (आरएनएस)। 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने की मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। लेकिन सुनवाई शुरू होते हीं स्थगित हो गई है। केंद्र सरकार ने अपना फैसला साझा करने के लिए कोर्ट से दो दिन का समय मांगा है। इस पर मामले को स्थगित करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, सीबीएसई से कहा है कि अगर उसने परीक्षा को आगे बढ़ाने का फैसला किया है और परीक्षा रद्द करने के लिए अपनी पिछले वर्ष की नीति का पालन नहीं करने का इरादा है तो उसके लिए उचित कारण भी बताएं। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 3 जून तक के लिए टाल दी है। सुप्रीम कोर्ट ने दो दिन के समय पर सहमति जताते हुए केंद्र और सीबीएसई से गुरुवार तक अपना फैसला साझा करने को कहा है। न्यायमूर्ति खानविलकर ने अटॉर्नी जनरल से कहा, आप एक निर्णय लें। लेकिन अगर आप परीक्षा आयोजित नहीं करने के लिए पिछले साल लिए गए निर्णय से विचलित हो रहे हैं, तो आपको हमें अच्छे कारण बताना चाहिए। पीठ ने कहा कि जो भी निर्णय उचित हो, वह लें। लेकिन जो चिंताएं व्यक्त की गई हैं। उन्हें ध्यान में रखें। याचिकाकर्ता का कहना है कि पिछले साल की नीति का पालन किया जाना चाहिए। यदि आप पिछले साल की नीति से हटकर निर्णय ले रहे हैं तो आपको उचित कारण बताना होगा। लगभग इसी तरह की स्थिति पिछले वर्ष में थी।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने नई कृषि प्रौद्योगिकियों एवं किस्मों का किया विमोचन

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत सरकार की सफलता के 7वर्ष पूरे होने के साथ-साथ प्रधानमंत्री जी के दृढ़ संकल्प के परिणामस्वरूप भारत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है।आमजन की भागीदारी देश के विकास में बढ़ रही है औरहर व्यक्ति के मन में एक जज्बा उत्पन्न हुआ है कि उसे भी अपनी योग्यता, दक्षता,ऊर्जा से देश केलिए कोई ना कोई काम करना चाहिए। तोमर ने कहा कि हमारे देश में खाद्यान्न की प्रचुरता है, यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के अनुसंधान, किसानों के परिश्रम व सरकार कीकृषि हितैषी नीतियों का सद्परिणाम है। हमें दलहन, तिलहन व बागवानी फसलों के क्षेत्र में और काम करने की जरूरत है। दलहन व तिलहन में आत्मनिर्भरता के लिए नई नीति आएंगी। प्रधानमंत्री जी ने इस बात पर बल दिया है। उनका कहना है कि आयात पर हमारी निर्भरता कम हो तथा हम कृषि उत्पादों का निर्यातज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। बीजों की नई किस्मों का इसमें विशेष योगदान होगा।

केंद्रीय मंत्री तोमर ने यह बात सोमवार को आईसीएआर की उपलब्धियों, प्रकाशनों, नई कृषि प्रौद्योगिकियों एवं कृषि फसलों की नई किस्मों की लॉन्चिंग तथा कृतज्ञ हैकाथॉन के विजेताओं को पुरस्कार वितरण के कार्यक्रम में कही। कृतज्ञमें प्रतियोगियों ने कृषि व सम्बद्ध क्षेत्रों के लिए एक से बढ़कर एक उपयोगी संरचनाएं सृजित कर अपनी योग्यता व क्षमता को साबित किया है।

तोमर नेआईसीएआर की तारीफ करते हुए कहा कि उसके वैज्ञानिक समग्रता से विचार कर रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों, वर्षा आधारित खेती वाले क्षेत्रों व अन्य प्रतिकूलपरिस्थितियों से हमारे बीज सामना कर सकें तथा किसानों की आय बढ़ा सकें एवं उत्पादन व उत्पादकता कोभी बढ़ाया जा सकें। फसल डायवर्सिफिकेशन का भी विषय विद्यमान है, सरकार इस दिशा में बहुत तेजी के साथ काम कर रही है। कृषि व सम्बद्धअधिकांश क्षेत्रों में दुनिया मेंभारत पहले या दूसरे नंबर पर है, गर्व है कि प्रधानमंत्री जी का चिंतन हमें इस ओर आगे बढ़ने के लिए तेजी सेप्रवृत कर रहा है और किसान भी पूरी उत्सुकता सेकाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कृतज्ञहैकाथॉनमें जिस तरह से अच्छे से अच्छे आविष्कार पेश किए गए हैं, उसे देखते हुए विश्वासपूर्वक कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान के नागरिकों में बड़ी से बड़ी परिस्थितियों का सामना करने व उनमें विजयी प्राप्त करने का सामर्थ्य है, यहीं भारत वर्ष की सबसे बड़ी पूंजी व ताकत है।कृषि का क्षेत्र अग्रणी भूमिका निभा सकें, इसमें आईसीएआर से संबंधित वैज्ञानिकगण, अनुसंधान केंद्र, वि.वि., छात्र, नई तकनीक, नए बीजों की किस्में ईजादकरने का निश्चित रूप से बहुत बड़ा महत्व है। इस दिशा में आईसीएआर जिम्मेदारी के साथ काम कर रहा है, यह प्रसन्नता व संतोष का विषय है। उन्होंने इसके लिए देशभर के संस्थानों की टीमों व केवीके की टीमों को बधाई व शुभकामाएं दी।

तोमर ने कहा कि मुंहपका-खुरपका रोग से देश के पशुओं को मुक्त कराने के लिए आईसीएआरसीरो-मॉनीटरिंग के माध्यम से महत्वपूर्ण सेवा कर रहा है। इसमें और तेजी लाने की आवश्यकता है। केवीके ने 5 करोड़ से ज्यादा किसानों तक अपनी पहुंच बनाई है, इसे भी बढ़ाने की जरूरत है। कृषि शिक्षा महत्वपूर्ण पहलू है, जिसके माध्यम से हमें कृषि क्षेत्र का समग्र विकास करना है। केंद्रीय मंत्री नेआईसीएआरको अंतरराष्ट्रीय राजा भूमिबोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार-2020; विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ), जेनेवा व संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा सम्मान व डिजीटल इंडिया पुरस्कार-2020 प्राप्त होने पर बधाई दी।

3 जून को केरल पहुंचेगा मानसून, 2 और 3 जून को राज्य में भारी बारिश का अनुमान

नई दिल्ली (आरएनएस)। मानसून 3 जून को केरल पहुंचेगा। 2 और 3 जून को यहां भारी बारिश की संभावना है। दिल्ली में रविवार को मौसम बदल गया और हल्की बारिश हुई। अगले 2-3 दिन ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक, एक के बाद एक आए दो चक्रवाती तूफानों के कारण इस साल कहीं हीटवेव नहीं चलेगी।

समुद्री तूफान ताऊ ते और यास की वजह से मध्यप्रदेश, यूपी, दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में मई में भी बारिश हो रही है। साथ ही बादल छाए होने की वजह से अधिकतम तापमान भी 40 डिग्री से नीचे बना हुआ है। रविवार शाम को दिल्ली के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी चली। सोमवार को यहां न्यूनतम तापमान सामान्य से तीन डिग्री कम 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बारिश के अनुमान के बावजूद दिन में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं, एयर क्वॉलिटी इंडेक्स 106 दर्ज किया गया।

बीती 27 मई को मौसम विभाग ने 31 मई को मानसून के केरल पहुंचने की संभावना जाहिर की थी। आमतौर पर मानसून के आने की तारीख 1 जून होती है। मौसम विभाग ने कहा था कि इस साल सामान्य बारिश का अनुमान है। जून से सितंबर के बीच होने वाली इस मानसूनी बारिश में चावल, मक्का, सोयाबीन और कपास की बुवाई होती है। इस सीजन में होने वाली बारिश पर देश की आधी खेती निर्भर करती है।

भारत में 1.52 लाख नये मामलों के साथ नये मामलों के घटने का चलन बरकरार

नई दिल्ली (आरएनएस)। भारत में दैनिक नये मामलों की संख्या में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। आज 1.52 लाख नये मामलों के साथ पिछले 50 दिनों में दैनिक नये मामलों की संख्या अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंची।

लगातार चौथे दिन कोविड-19 के नये मामलों की संख्या दो लाख से कम दर्ज की गयी। पिछले 24 घंटे में 1,52,734 नये मामले दर्ज किए गए। भारत में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या लगातार घट रही है। सक्रिय मामलों की संख्या गिरकर आज 20,26,092 हो गयी। पिछले 24 घंटे में सक्रिय मामलों की संख्या में कुल 88,416 की कमी आयी है। यह अब देश के कुल कोविड पॉजिटिव मामलों का केवल 7.22 प्रतिशत है।

साथ ही लगातार 18वें दिन भारत में बीमारी से स्वस्थ होने वाले लोगों की दैनिक संख्या कोविड-19 के दैनिक नए मामलों से ज्यादा हैं। पिछले 24 घंटे में बीमारी से 2,38,022 लोग स्वस्थ हुए हैं। पिछले 24 घंटे में दैनिक नये मामलों की तुलना में बीमारी से 85,288 ज्यादा लोग स्वस्थ हुए हैं। भारत में महामारी शुरू होने के बाद से पहले ही कुल 2,56,92,342 लोगों में कोविड-19 ठीक हो चुका है और पिछले 24 घंटे में बीमारी से कुल 2,38,022 लोग स्वस्थ हुए हैं। बीमारी से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर भी बेहतर होकर 91.60 प्रतिशत हो गयी है। भारत में पिछले 24 घंटे में कुल 16,83,135 जांच हुई जिसके साथ अब तक हुए जांच की कुल संख्या 34.48 करोड़ है। जहां एक तरफ पूरे देश में कोविड की जांच बढ़ गयी है, वहीं दूसरी तरफ साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट भी लगातार घट रहा है।

ईपीएफओ ने अपने सदस्यों को दूसरा कोविड-19 एडवांस लेने की अनुमति दी

नई दिल्ली (आरएनएस)। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान अपने ग्राहकों को सहयोग देने के लिए अपने सदस्यों को दूसरे नन-रिफंडेबल (गैर-वापसी) कोविड-19 एडवांस (अग्रिम) का लाभ उठाने की अनुमति दी है। महामारी के दौरान सदस्यों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष निकासी का प्रावधान मार्च, 2020 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के अंतर्गत किया गया था। इस विषय में श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 में संशोधन करके सरकारी गजट में अधिसूचना के माध्यम से पैराग्राफ 68एल के तहत सब-पैरा (3) जोड़ा गया था।

इस प्रावधान के अंतर्गत तीन महीने के लिए मूल वेतन और महंगाई भत्ते की सीमा तक गैर-वापसी योग्य निकासी या ईपीएफ खाते में सदस्य की जमा राशि का 75 प्रतिशत तक, जो भी कम हो, दिया जाता है। सदस्य कम राशि के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।

कोविड-19 एडवांस महामारी के दौरान ईपीएफ सदस्यों को बड़ी सहायता रही है विशेषकर उन लोगों के लिए जिनका मासिक वेतन 15,000 रुपए से कम है। ईपीएफओ ने अब तक 76.31 लाख कोविड एडवांस दावों का निपटान किया है और कुल 18,698.15 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं।

कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान हाल में म्यूकोर्मिकोसिस या ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया गया है। ऐसे कठिन समय में ईपीएफओ का प्रयास अपने सदस्यों की मदद करना रहा है ताकि सदस्य अपनी वित्तीय आवश्यकताएं पूरी कर सकें। पहला कोविड-19 एडवांस का लाभ उठाने वाले सदस्य दूसरे कोविड-19 एडवांस का विकल्प भी चुन सकते हैं। दूसरे कोविड-19 एडवांस का प्रावधान और प्रक्रिया पहले एडवांस की तरह ही है।

संकट के समय में सदस्यों के लिए वित्तीय सहयोग की आवश्यकता पर विचार करते हुए कोविड-19 दावों को उच्च प्रथमिकता देने का निर्णय लिया गया है। ईपीएफओ दावों की प्राप्ति के तीन दिनों के अंदर उन्हें निपटाने के लिए संकल्पबद्ध है। ईपीएफओ ने इसके लिए ऐसे सभी सदस्यों के संबंध में एक प्रणाली संचालित ऑटो-क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया की तैनाती की है, जिनकी केवाईसी आवश्यकताएं सभी दृष्टि से पूर्ण हैं। निपटान का ऑटो-मोड ईपीएफओ को 20 दिनों के भीतर दावों को निपटाने के लिए वैधानिक आवश्यकता की जगह दावा निपटान चक्र को केवल 3 दिनों तक कम करने में सक्षम बनाता है।

एनटीपीसी स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए स्थानीय प्रशासन का कर रही है सहयोग

नई दिल्ली (आरएनएस)। एनटीपीसी, विद्युत मंत्रालय के तहत एक महारत्न सीपीएसयू है। कंपनी की हजारीबाग स्थित पकरी बरवाडीह कोयला खनन परियोजना, सीएसआर के तहत रांची के बाहरी इलाके में स्थित कोविड केयर अस्पताल के आईटीकेआई टीबी सेनेटोरियम में 300 बिस्तरों के लिए केंद्रीकृत मैनिफोल्ड ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम तैयार कर रही है। देश के साथ-साथ झारखंड राज्य में भी कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के तहत गंभीर मामलों में भारी वृद्धि हुई है। और इसके परिणामस्वरूप रांची और हजारीबाग के सभी प्रमुख अस्पतालों में बिस्तर की कमी हो गई है। जिसमें राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) भी शामिल है। इन परिस्थितियों को देखते हुए कंपनी द्वारा यह पहल की गई है।

यह अस्पताल कोविड क्लस्टर देखभाल केंद्र में से एक है। जिसका उद्देश्य कोविड-19 रोगियों का उपचार करना है। ताकि दूसरी लहर की वजह से शहर के अस्पतालों पर मरीजों के पड़ रहे दबाव को कम किया जा सके। एनटीपीसी कोविड-19 के प्रसार को कम करने के लिए मौजूदा बुनियादी सुविधाओं में सुधार कर रहा है। इसके अलावा कंपनी रांची स्थित रिम्स अस्पताल को सीएसआर पहल के तहत वित्तीय सहायता के साथ कोविड उपचार के लिए सहायक उपकरणों के साथ 40 जंबो सिलेंडर, 600 ऑक्सीजन युक्त बिस्तरों के लिए ऑक्सीजन पाइपिंग सिस्टम की स्थापना के लिए सहायता प्रदान कर रही है।

जल जीवन मिशन के तहत 2021-22 के लिए गुजरात को 3,411 करोड़ रुपये अनुदान के रूप में आवंटित किए

नई दिल्ली (आरएनएस)। हर घर जल के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अर्थात् प्रत्येक घर को नियमित और दीर्घकालिक आधार पर सुनिश्चित नल के पानी की आपूर्ति प्रदान करने के लिए, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार ने वर्ष 2021-22 के लिए जल जीवन मिशन के तहत गुजरात राज्य को 3,410.61 करोड़ रुपये अनुदान के रूप में आवंटित किए हैं। इस आवंटन की पहली किस्त के रूप में 852.65 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गुजरात राज्य को जलापूर्ति के लिए अनुदान आवंटन में चार गुना वृद्धि को मंजूरी दी। वर्ष 2019-20 के लिए केंद्र सरकार का आवंटन 390.31 करोड़ रुपये था, जिसे 2020-21 में बढ़ाकर 883.08 करोड़ रुपये कर दिया गया।

जीवन बदलने वाला जल जीवन मिशन-हर घर जल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 15 अगस्त, 2019 को शुरू किया गया था ताकि 2024 तक गांवों में रहने वाले लोगों, विशेषकर महिलाओं और लड़कियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए हर ग्रामीण घर में पीने के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। गुजरात में, 2020-21 के दौरान, 10.94 लाख ग्रामीण परिवारों को नल के पानी के कनेक्शन प्रदान किए गए हैं और 2021-22 में भी राज्य की योजना 10 लाख से अधिक घरों में नल के पानी के कनेक्शन प्रदान करने की है। गुजरात में 92.92 लाख ग्रामीण परिवार हैं, जिनमें से अब 77.21 लाख (83 प्रतिशत) घरों में पाइप से पानी की आपूर्ति की जा रही है।

पिछले वर्ष केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ समीक्षा बैठक के दौरान, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने राष्ट्रीय लक्ष्य से दो साल पहले, 2022 तक राज्य के प्रत्येक ग्रामीण घर में नल के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन मिशन को तेजी से और बड़े पैमाने पर लागू करने का वादा किया था।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पर जोर दिया है। जल जीवन मिशन इस सिद्धांत के बेहतरीन उदाहरणों में से एक है और यह सुनिश्चित करने का प्रयास है कि गांव के हर घर में नल के पानी की आपूर्ति हो। गुजरात में करीब 18 हजार गांवों में से 6700 से ज्यादा गांवों में हर घर में नल से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जा चुकी है। 2020-21 में, प्रत्येक घर को नल के पानी का एक चालू कनेक्शन प्रदान करके लगभग 5,900 गांवों को हर घर जल वाला बनाया गया था। राज्य के 5 जिलों में, प्रत्येक ग्रामीण परिवार में नल के पानी की आपूर्ति है।

राष्ट्रीय जल जीवन मिशन द्वारा अनुमोदित राज्य की वार्षिक कार्य योजना के अनुसार, अन्य 18 जिलों तथा 6,400 और गांवों में नल के पानी की आपूर्ति के साथ 100 प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित होगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण कोई भी छूटे नहीं के अनुरूप राष्ट्रीय जल जीवन मिशन राज्य सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पाइप से जलापूर्ति व्यवस्था वाले सभी गांवों में प्राथमिकता के साथ हर घर को नल का पानी कनेक्शन दिया जाए। उम्मीद है कि अगले कुछ महीनों में गुजरात के 12 हजार से ज्यादा गांव और 23 जिले हर घर जल वाले गांव बन जाएंगे यानी हर घर में नल के पानी की आपूर्ति शुरू हो जाएगी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा घोषित 100 दिनों के अभियान के तहत और 2 अक्टूबर, 2020 को स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों और आश्रम शालाओं में नल के पानी की आपूर्ति प्रदान करने के लिए शुरू किये गये अभियान के अंतर्गत, राज्य सरकार ने सभी 29,754 ग्रामीण स्कूलों और 42,279 आंगनबाड़ी केंद्रों में नल के पानी के कनेक्शन सुनिश्चित किए। इस योजना के अंतर्गत 98.5 प्रतिशत स्कूलों और लगभग 91 प्रतिशत आंगनबाड़ी केंद्रों में हाथ धोने की सुविधा भी प्रदान की है।